



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 1983/चैत्र 29, 1905

No. 148]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 1983/CHAITRA 29, 1905

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

विदेश-कर प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1983

आय-कर

सा० का० नि० 342(अ).—आय और पूंजी पर करों से सम्बन्धित
बीहरे कराधान का परिवर्जन और राजस्थानीय अपवंचन के निवारण के
लिए भारत गणराज्य की सरकार और गवर्नमेंट आफ दी डेमोक्रेटिक
सोशलिस्ट रिपब्लिक आफ श्रीलंका के बीच हुई, इससे उपायय
कन्वेंशन का अनुममर्थन कर दिया गया है और उक्त कन्वेंशन के अनुच्छेद
29 द्वारा यथा अपेक्षित अनुममर्थन निम्नलिखितों का आदान-प्रदान कर
दिया गया है :

घन; केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का
43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) अतिकार अधिनियम, 1964
(1964 का 7) की धारा 24 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करने हुए, यह निवेदन देती है कि उक्त कन्वेंशन के सभी उपबन्धों को
भारत के संघ में प्रभावी किया जाएगा।

भारतीय गणराज्य की सरकार

और श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार
के बीच

आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में बीहरे कराधान के परिहार
और राजस्व के अपवंचन को रोकने के लिए
अभिसमय

आय तथा पूंजी पर करों के सम्बन्ध में बीहरे कराधान के परिहार
और राजस्व के अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार
तथा श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच अभि-
समय

भारत गणराज्य की सरकार, तथा श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी
गणराज्य की सरकार, आय तथा पूंजी पर करों के सम्बन्ध में बीहरे
कराधान के परिहार और राजस्व के अपवंचन को रोकने के लिए
अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से, नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई
हैं:—

अनुच्छेद 1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक अथवा
दोनों संबिदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर

1. यह अभिसमय प्रत्येक संबिदाकारी राज्य की ओर से आय तथा
पूंजी पर लगाये गये करों के मामले में लागू, होगा फिर चाहे वे
कर किसी भी तरह से लगाये जाते हों।

2. कुल आय, कुल पूंजी, अथवा आय अथवा पूंजी के तत्वों पर लगाये
गये सभी करों जिसमें चयन अथवा अचयन सम्पत्ति के अंतरण

हुए अभिवाओं पर कर सम्मिलित है, तथा पूंजी के मूल्यों में हुई वृद्धि पर लगे करों—को—अल्प-और-पूजी पर कर समझा जायेगा।

3. यह अभिसमय जिन वर्तमान करों पर लागू होगा वे हैं :—

(क) श्री लंका में :

(i) आयकर, जिसमें ग्रेटर कोलम्बो इकोनॉमिक कर्मभवन से नाइसेस प्राप्त उद्यमों के कुल व्यापार पर आधारित आयकर सम्मिलित है ; और

(ii) धन कर

(जिसे इसके बाद "श्रीलंका कर" कहा गया है)

(ख) भारत में :

(i) आयकर जिसमें उस पर लगाया गया कोई अधि-भार शामिल है ;

(ii) अतिकर, और

(iii) धन कर

(जिसे इसके बाद 'भारतीय कर' कहा गया है)

(4) यह अभिसमय, किन्हीं समरूप अथवा सारनः जैसे ही करों पर भी लागू होगा जो दोनों में से किसी भी सविदाकारी राज्य द्वारा, वर्तमान करों के अनुरिक्त अथवा उनके स्थान पर, वर्तमान अभिसमय पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद लगाये गये हों। सविदाकारी राज्यों के लक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो ;

(क) 'सविदाकारी राज्य' और 'दूसरे सविदाकारी राज्य' शब्दों में संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार श्रीलंका अथवा भारत अभिप्रेत है ;

(ख) 'व्यक्ति' शब्द में कोई व्यक्ति, कम्पनी तथा व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय शामिल है ;

(ग) 'कम्पनी' शब्द से कोई ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई इकाई अभिप्रेत है जो कर प्रयोजनों के लिए निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है ;

(घ) 'एक सविदाकारी राज्य का उद्यम' तथा 'दूसरे सविदाकारी राज्य का उद्यम' शब्दों में क्रमशः सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम और दूसरे सविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित उद्यम अभिप्रेत है ;

(ङ) 'अन्तर्राष्ट्रीय वातायान' शब्दों से किंगी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा परिवहन अभिप्रेत है जो ऐसे किसी उद्यम द्वारा संचालित हों जिसकी प्रभावी प्रबंध व्यवस्था का स्थान किसी सविदाकारी राज्य में हो, सिवाय इसके कि जब जलयान अथवा वायुयान अन्य सविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच चलाया जाता हो,

(च) 'राष्ट्रिक' शब्द से अभिप्रेत है :—

(i) सविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला व्यक्ति ;

(ii) विधिक व्यक्ति भागीदारी अथवा संस्था जो सविदाकारी राज्य में प्रचलित कानूनों से इस प्रकार अपनी हैमियत प्राप्त करता है

(छ) "लक्षम प्राधिकारी" शब्दों से अभिप्रेत है :

(i) श्री लंका के मामले में, कमिशनर जनरल ऑफ इंग्लैण्ड रेवेन्यू ;

(ii) भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)।

2. जहां तक किसी सविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय को लागू करने के संबंध है, किसी शब्द का, जो वहां परिभाषित नहीं हुआ हो, संदर्भ की अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर, वह अर्थ होगा जो उस राज्य के कानूनों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है, जो इस अभिसमय के विषय है।

अनुच्छेद 4

आर्थिक अधिवास

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए, सविदाकारी राज्य का निवासी शब्दों से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जो उस राज्य के कानून के अंतर्गत, उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध स्थान अथवा इस प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण उसमें कर लगने योग्य है। किन्तु इस शब्द से ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर उस राज्य के कानूनों से आय के संबंध में ही अथवा वहां स्थित पूंजी के संबंध में कर लग सकता है।

2. जहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों सविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसकी हैमियत निम्नानुसार निश्चित की जाएगी :

(क) वह उस सविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसको स्थायी गृह उपलब्ध हो। यदि उसको दोनों राज्यों में स्थायी निवास गृह उपलब्ध है तो वह उस राज्य का निवासी माना जायेगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र)

(ख) यदि उस सविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, निष्पत्ति नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसको किसी भी सविदाकारी राज्य में स्थायी निवास गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस सविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा जिसमें उसका व्यवहारिक आवास हो ;

(ग) यदि उसका व्यवहारिक आवास दोनों सविदाकारी राज्यों में है अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं है तो वह उस सविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा, जिसका वह राष्ट्रिक है ;

(घ) यदि वह दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो सविदाकारी राज्यों के लक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपबंधों के कारण से, व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों सविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस सविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है।

अनुच्छेद 5

स्थायी स्थापना

1. इन अभिसमय के प्रयोजनों के लिए 'स्थायी स्थापना' शब्दों से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जहाँ उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. 'स्थायी स्थापना' शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) प्रबन्ध का स्थान;
- (ख) माखा;
- (ग) कार्यालय;
- (घ) कारखाना;
- (ङ) कर्मशाला;
- (च) खान, तेल अथवा गैस कूप, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
- (छ) कृषि अथवा कृषि सम्पदा अथवा बागान;
- (ज) भवन स्थल अथवा निर्माण अथवा सामूहिक परियोजना या 183 दिन से अधिक अवधि के लिए विद्यमान रहनी हो;
- (झ) किसी उद्यम द्वारा कर्मचारियों अथवा अन्य कामिकों के के जरिये ऐसे स्थान पर ऐसी सेवाओं का प्रस्तुत किया जाना जिनमें परामर्श संबंधी सेवाएं भी शामिल हैं, जहां उस तरह के कार्य वेश के अन्दर 12 मास की किसी भी अवधि के भीतर कुल 183 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए लागू रहनी है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के हाते हुए भी, 'स्थायी स्थापना' शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जायेगा।

- (क) उद्यम के माल पण्यों के केवल भण्डारकरण, प्रदर्शन अथवा सुपुर्दगी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;
- (ख) उद्यम के माल अथवा पण्यों के भण्डारकरण, प्रदर्शन अथवा सुपुर्दगी के अनन्य प्रयोजनार्थ स्टोक रखना;
- (ग) अन्य उद्यम द्वारा संसाधित करने के अनन्य प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्यों का स्टोक रखना;
- (घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्यों का क्रय करने अथवा सूचना संग्रह के अनन्य प्रयोजनार्थ कारोबार का नियत स्थान रखना;
- (ङ) उद्यम के व्यापार अथवा कारोबार में विज्ञापन, सूचना देने अथवा ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के अनन्य प्रयोजनार्थ जो प्रारम्भिक अथवा मध्यम किस्म के हैं कारोबार का नियत स्थान रखना।

4. अन्य संबिदाकारी राज्य के उद्यम की ओर से किसी संबिदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति जो स्वतंत्र हैसियत के अधिकारी से भिन्न हो और जिस पर इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (6) की व्यवस्था लागू होती हो—प्रथमोक्त राज्य में उस उद्यम की स्थाई स्थापना माना जायेगा यदि वह उस राज्य में उद्यम के नाम से संबिदा करने का प्राधिकार रखता है और उसका नियमित रूप से प्रयोग करता है, जब तक कि उसके क्रियाकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्यों के क्रय तक ही सीमित नहीं हो।

5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी, एक संबिदाकारी राज्य का कोई भीमा उद्यम, पुनः बीमा से संबंधित उद्यम को छोड़कर, अन्य संबिदाकारी राज्य में स्थायी स्थापना माना जायेगा यदि वह उस अन्य राज्य की सीमा में बीमे की किस्त बसूल करता है अथवा स्वतंत्र हैसियत के एजेंट से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा

जिम पर इस अनुच्छेद का पैराग्राफ (6) लागू होता है, वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है।

6. एक संबिदाकारी राज्य के उद्यम की अन्य संबिदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से स्थायी स्थापना नहीं मानी जाएगी कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करती है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के काम सामान्य रूप में कर रहे हों। किन्तु जब इस प्रकार के एजेंट के क्रियाकलाप उस उद्यम की ओर से पूर्ण रूप से अथवा लगभग पूर्ण रूप से किये जाते हैं तो उसे इस पैराग्राफ के अधिप्राय के अन्तर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं माना जायेगा।

7. इस तथ्य से कि कोई कंपनी जो किसी संबिदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कंपनी का नियंत्रण करती है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संबिदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी स्थापना के माध्यम से अथवा अन्यथा) व्यापार अथवा कारोबार चलाती है उन दोनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी स्वतः दूसरी कंपनी की स्थायी स्थापना नहीं बन जाएगी।

अनुच्छेद 6

अचल संपत्ति से आय

1. अचल संपत्ति से आय पर उस संबिदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है।

2. 'अचल संपत्ति' शब्दों की परिभाषा उस संबिदाकारी राज्य की विधि के अन्तर्गत की जायेगी, जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इन शब्दों में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल संपत्ति के उप साधन के रूप में संपत्ति, कृषि और अनसंपत्ति में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबन्ध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार, खनिज भण्डार, स्त्रोत तथा अन्य प्राकृतिक साधनों का संचालन अथवा संचालन अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार पोट नौकाए तथा विभाग अचल संपत्ति नहीं माने जायेंगे।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के उपबन्ध, अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग से, किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होगी।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) और (3) के अन्वये किसी उद्यम की अचल संपत्ति से आय और व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के लिए इस्तेमाल में आने वाली अचल संपत्ति से होने वाली आय पर भी लागू होगी।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. किसी संबिदाकारी राज्य के उद्यम के लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जाएगा, जब तक वह उद्यम अन्य संबिदाकारी राज्य में बहा निश्चित किसी स्थायी स्थापना के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता हो। यदि उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार कर रहा हो, तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा परन्तु केवल उसने ही लाभों पर कर लगाया जा सकेगा जो निम्नलिखित के कारण हुए माने जा सकते हैं:—

(क) उस स्थायी स्थापना,

(ख) उस दूसरे राज्य में वैसे ही अथवा उसी प्रकार के माल अथवा पण्यों की बिन्ती जैसे कि उस स्थायी स्थापना के माध्यम से बेचे जाते हैं, अथवा

(ग) उस दूसरे राज्य में किये गये वैसे ही अथवा उसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य जैसे उस स्थायी स्थापना के माध्यम से किये जाते हैं।

उपयुक्त उप-पैराग्राफ (ख) और (ग) के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब उद्यम यह सिद्ध कर देता है कि ऐसी बिक्री अथवा क्रियाकलाप स्थायी स्थापना के कारण हुए नहीं माने जा सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) के उपबंधों के अध्याधीन, जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी स्थापना के माध्यम से कारोबार करता है, वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी स्थापना के कारण उसको उन लाभों का होना माना जायेगा जिनके प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती, जब वह, उन्हीं अथवा वैसे ही परिस्थितियों के अस्तित्व उन्हीं अथवा वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित तथा अलग उद्यम होता, और जिस उद्यम की वह स्थायी स्थापना है, उसके साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता होता।

3. किसी स्थायी स्थापना के लाभों के निर्धारण में व्ययों की कटौतियों की स्वीकृति दी जायेगी, जो स्थायी स्थापना के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए गए हों, और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यपार्षीय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहाँ स्थायी स्थापना स्थित है अथवा अन्यत्र तथापि स्थायी स्थापना द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतिपुष्टि से भिन्न रूप में) पेटेंट अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में स्वामित्व, फीस अथवा अन्य ऐसी ही अदायगियों के रूप में, अथवा विशिष्ट सेवा सम्पादन अथवा प्रबन्ध के लिए कमीशन के रूप में अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी स्थापना को उधार दिये गये धन पर ब्याज के रूप में यदि कोई रकम अवा की गयी हों, तो उनके संबंध में ऐसी किसी कटौती की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। इसी प्रकार, स्थायी स्थापना के लाभों के निर्धारण में उन रकमों को हिसाब में नहीं लिया जायेगा जो स्थायी स्थापना द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतिपुष्टि से भिन्न रूप में), स्थायी स्थापना द्वारा पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में स्वामित्व फीस अथवा अन्य ऐसी ही अदायगियों के रूप में, अथवा विशिष्ट सेवा सम्पादन के लिए अथवा प्रबन्ध के लिए कमीशन के रूप में अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, अन्य मामलों में, उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके किसी अन्य कार्यालयों में से किसी को उधार दिये गये धन पर ब्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को प्रभारित की गयी हो।

4. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न अंगों के प्रति अनुभाजन के आधार पर, किसी स्थायी स्थापना के कारण माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रथा हो, वहाँ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) की कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसी यथा सही प्रभाजन पद्धति से, कर लगाने वाले लाभों को निश्चित करने से निर्धारित नहीं करेगी तथापि, प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुसार होगा।

5. कोई लाभ मात्र इस कारण स्थायी स्थापना को हुए नहीं माने जायेगे कि उस स्थायी स्थापना द्वारा उद्यम के लिए भाल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी गई हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी स्थापना के कारण माने जाने वाले लाभों को अब तक, उसी पद्धति से वर्णानुवर्ण निर्धारित किया जायेगा जब तक कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।

7. जहाँ लाभों में आय की वे सदैव शामिल हों, जिनका इस अध्याय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

जहाजरानी और विमान परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोत अथवा विमान संचालन से प्राप्त लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लगाया जायेगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है।

2. पैराग्राफ (1) के उपबंधों के रहने हुए भी, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोत संचालन से प्राप्त लाभों पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है जिसमें इस प्रकार का संचालन किया जाता है; किन्तु इस प्रकार प्रभारित कर उस राज्य के आन्तरिक कानून द्वारा अन्य प्रकार से लगाये गये कर से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

परन्तु शर्त यह है कि कर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, इस प्रकार के लाभों को एक ऐसी राशि माना जायेगा जो उन बरों से अधिक नहीं होगी जिनकी इस प्रकार के लाभों की संगणना के लिए अलग अलग राज्यों के करानुसंग कानून में वर्तमान में व्यवस्था है।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) और (2) के उपबंध, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोत अथवा विमान संचालन में लगे उद्यमों द्वारा किसी पूल सेवा, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय यातायात एजेंसी में भाग लेने से होने वाले लाभों के संबंध में भी इसी प्रकार लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजन के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोतों अथवा विमान संचालन से संबंधित निधियों पर ध्याज को इस प्रकार के विमान के संचालन से आय के रूप में माना जाएगा, और अनुच्छेद 11 के अनुबंध इस प्रकार के ध्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

5. यदि किसी जहाजरानी उद्यम के प्रभावी प्रबंध का स्थान किसी पोत पर हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जायेगा जिसमें पोत का मूल बन्दरगाह स्थित है, और अगर उस पोत का ऐसा कोई मूल बन्दरगाह न हो, तो वह उस राज्य में स्थित माना जायेगा जिस राज्य का पोत का संचालन निवासि है।

अनुच्छेद 9

सम्बद्ध उद्यम

1. जहाँ:

(क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध नियंत्रण अथवा पूंजी में, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग देता है, अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम में और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम में प्रबन्ध, नियंत्रण अथवा पूंजी में भाग लेते हैं,

और दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं, जो किसी शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहाँ ऐसे कोई लाभ जो, इन शर्तों के नहीं होने की दृष्टि से, उन उद्यमों में से एक को प्राप्त हुए होंगे, किन्तु इन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित होंगे या सक्की और वे नवतुम्हार करायेय हो सकेंगे।

2. जहाँ एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और मनुसार कर लगाता है, जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य का एक उद्यम उस दूसरे राज्य में कर लगाता है और इस प्रकार सम्मिलित किये गये लाभ वे लाभ हैं जो प्रथमोक्त राज्य के उद्यम का प्राप्त हुए होते यदि वो उद्यमों के बीच लगाई गई बातें वे हानियाँ जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई जाती हैं, तब वह अन्य राज्य उन लाभों पर जहाँ पर प्रतिष्ठित कर की राशि का सम्मिलित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन का विनिश्चय करने में, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का भी आवश्यक ध्यान रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो संविदाकारी राज्यों के मध्य प्राधिकारी, एक दूसरे से परामर्श करेगा।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. जो कंपनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये गये लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी कराधेय होंगे जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है और यह कर उस राज्य के कानून के अनुसार लगाया जाएगा, किन्तु इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त लाभांशों शब्द का अभिप्राय, शेयरों, खानशेयरों, संस्थापक शेयरों अथवा ऐसे अन्य अधिकारों से, जो ऋण वाले नहीं हैं और लाभों में सहभागी हो प्राप्त आय से तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर उस संविदाकारी राज्य के कराधान कानून द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लगाये जाने वाले की तरह से ही कर लगाया जाता है, जिसकी विवरण करने वाली कंपनी निवासी है।

4. पैराग्राफ (1) तथा (2) के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, द्वारा संविदाकारी राज्य में व्यापार करता है जिसकी, लाभांश अदा करने वाली कंपनी, वह स्थित एक स्थायी स्थापना के माध्यम से, निवासी है और जिस धारिता के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी स्थापना से प्रभावी रूप से सम्बन्धित है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, जहाँ कंपनी द्वारा किये गये लाभांशों पर, जहाँ तक कि ऐसे लाभांशों को छोड़कर जो दूसरे राज्य के निवासी को अदा किये गये हों अथवा जहाँ तक कि जिससे धारिता के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह उस राज्य में स्थित इस प्रकार के स्थायी स्थापना से प्रभावी रूप से सम्बन्धित है, उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा, और न ही कंपनी के अतिरिक्त लाभों पर अतिरिक्त लाभकर की किस्म का कोई कर लगाया जाएगा, यहाँ अदा किये गये लाभांश अथवा अतिरिक्त लाभ पूर्णतः अथवा अल्पतः उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य से अर्जित होने वाले तथा दूसरे राज्य के निवासी को अदा किये जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में

यह उद्भूत होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रभावित कर की राशि ब्याज की सकल रकम से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के बावजूद एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट दी जाएगी यदि :

(क) ब्याज अदा करने वाला उस संविदाकारी राज्य की सरकार हो अथवा उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण हो, अथवा

(ख) ब्याज दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण की पूर्णतः स्वामित्व वाली किसी एजेंसी अथवा किसी माध्यम (जिसमें वित्तीय संस्थान शामिल है) का अदा किया गया हो।

4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से सरकारी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों, चाहे उनको लाभों में भागीदारी का अधिकारी प्राप्त हो अथवा नहीं, और हर प्रकार के ऋण बावों से प्राप्त आम और साध हो सभी अन्य ऐसी आय से अभिप्राय है, जो जिस संविदाकारी राज्य में आय उद्भूत हुई हो, उस राज्य के कराधान कानून के अनुसार उधार दिये गये धन से प्राप्त आय से समाविष्ट की गई हो।

5. पैराग्राफ (1) से (3) के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थिति किसी स्थानीय प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यापार चलाता हो और जिन दावों के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वो इस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान से प्रभावी रूप से संबंधित हों। इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहाँ ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य से उसका एक स्थायी प्रतिष्ठान है, जिसके संबंध में वह ऋण निरा गया था जिस पर ब्याज की अदायगी की गई है, और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा वसूल किया जाता है तब वह ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत माना जाएगा जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

7. जहाँ ब्याज अदा करने वाले हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋण बावों का ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिये इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी प्रतीत होती हो, यहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम बर्गित रकम पर लागू होंगे ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 12

रायल्टी

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी का अदा की गई रायल्टियों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, ऐसी रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत होती हैं, और उसी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया

जा सकेगा किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टी का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायल्टियों की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “रायल्टियां शब्द” से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों जिनमें चलचित्र फिल्में अथवा दूर दर्शन अथवा प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेप शामिल हैं, कोई पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाईन अथवा माऊल प्लान, गुण फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिकूल के रूप में अथवा औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) तथा (2) के उपबंध उस हालत में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टी का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और संविदाकारी राज्य में जिसमें रायल्टियां उद्भूत होती हैं वहां पर स्थित स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यापार चलाता है तथा जिस अधिकार अथवा संपत्ति के बारे में रायल्टियों की अदायगी की जाती है, ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान से कारगर रूप से संबंधित है, ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे।

5. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियां उद्भूत हुई मानी जाएगी, यदि रायल्टी अदा करने वाले राज्य स्वयं कोई स्थायी प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु जहां रायल्टियां अदा करने वाले व्यक्ति का चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके संबंध में रायल्टी अदा की गई थी और इस प्रकार की रायल्टियां उस स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा उद्भूत हुई हैं तब ऐसी रायल्टियां उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत मानी जाएगी, जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

6. जहां, रायल्टी अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गयी रायल्टियों की रकम, उनके ऐम इन्वेस्टमेंट, अधिकार अथवा सूचना का ध्यान में रखते हुए, जिसके लिये वे रायल्टियां अदा की जाती हैं उस रकम से बहुत जाती है जिसके लिये इस प्रकार के संबंध न होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अधिभाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का अनुपालन करने हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 13

पूर्वजगत लाभ

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ (2) में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ पर कर दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

2. चल संपत्ति के अन्तरण से, जो उस स्थायी प्रतिष्ठान की व्यापारिक संपत्ति के अंग के रूप में एक संविदाकारी राज्य में स्थित है जिसमें ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान (अकेले अथवा संपूर्ण उत्पन्न के साथ) के अन्तरण से होने वाले लाभ भी शामिल हैं जिन पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलाये जाने वाले जलपोतो अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलपोतो अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में काराधोग होंगे जिनमें उत्पन्न के कारगर प्रबंध का स्थान स्थित हो।

4. किसी कंपनी के स्टॉकों तथा शेयरों के अन्तरण से प्राप्त लाभ पर कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा जिसमें वे जारी किये गये हों।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) से (4) में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी संपत्ति पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगाया जाएगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

6. ‘अन्तरण’ शब्द का अर्थ संपत्ति का विक्रय, विनिमय, अन्तरण अथवा त्याग अथवा उसमें किसी भी अधिकार की समाप्ति अथवा अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त किसी भी कानून के अन्तर्गत उसका अनिवार्य अधिग्रहण है।

अनुच्छेद 14

स्वतंत्र व्यवस्थित सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को व्यावसायिक सेवाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतन्त्र कार्य कलापों के संबंध में प्राप्त हुई आय पर कर केवल उसी राज्य में लगेगा जब तक कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य में 12 माह की किसी ऐसी अवधि के भीतर कुल मिलाकर 120 दिनों से अधिक का अवधि अथवा अवधियों के लिए मौजूद नहीं रहा हो जिसमें ऐसी आय पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी लग सकता हो।

2. ‘व्यावसायिक सेवाएं’ शब्दों में स्वतन्त्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, यकीनों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दन्त-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतन्त्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 15

पारिश्रमिक व्यवस्थित सेवाएं

अनुच्छेद 16, 18 और 19 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य को, नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त वेतन, मंजूरी तथा अन्य इस प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में न हो। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में हो तो उससे प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रयुक्त नियोजन के संबंध में, प्राप्त पारिश्रमिक पर कर, केवल प्रभाविताखत राज्य में ही लगेगा यदि :

- (क) प्राप्तकर्ता 12 माह की किसी अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन की अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा है, और
- (ख) पारिश्रमिक की अदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई हो जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, और
- (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन न किया गया हो, जो कि उस नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलपोत पर अथवा वायुयान पर किये गये नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिनमें उस उत्पन्न की प्रभावी प्रबंध व्यवस्था है।

अनुच्छेद 16**निवेशक-मुलक**

संविदाकारी राज्य के निवासियों द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य का हस्ताक्षर से जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त निदेशक फॉस तथा इसी प्रकार की अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 17**कलाकार और खिलाड़ी**

1. अनुच्छेद 14 तथा 15 के उपबंधों के होते हुए भी, लोक मनोरंजनकर्त्ताओं (जैसे थियेटर, चल-चित्र रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार तथा संगीतकार) अथवा खिलाड़ियों को अपनी हस्तियत से अपने वैयक्तिक कार्यों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें ऐसे कार्य किये गये हों;

किन्तु ऐसी आय पर उक्त संविदाकारी राज्य में कर नहीं लग सकेगा, यदि लोक मनोरंजनकर्त्ताओं अथवा खिलाड़ियों को उस राज्य की यात्रा का व्यय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः, दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः अथवा पर्याप्त, किया गया हो।

2. जहाँ मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा उसकी वैयक्तिक क्रिया-कलापों के संबंध में प्राप्त आय मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहाँ अनुच्छेद 7, 14 तथा 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस आय पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिस राज्य में मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे क्रिया-कलाप किये जाते हैं।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए 'सरकार' शब्द में दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की राज्य-सरकार, राज-नीतिक उपमंडल अथवा स्थायी प्राधिकरण सम्मिलित माने जायेंगे।

अनुच्छेद 18**सरकारी सेवा**

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिये की गई सेवाओं के संबंध में अदा किया गया पेन्शन से भिन्न पारिश्रमिक केवल उस राज्य में ही कराधेय होगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर कर केवल दूसरे राज्य में ही लगेगा यदि उस दूसरे राज्य में सेवाएं की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी हो जो :

- (i) उस राज्य की राष्ट्रिक हो, अथवा
- (ii) मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को अदा की गई किसी भी प्रकार की पेन्शन पर कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा।

3. अनुच्छेद 15, 16 तथा 19 के उपबंध किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे कारोबार के सम्बन्ध में की गई सेवाओं से सम्बन्धित पारिश्रमिक तथा पेन्शन पर लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये 'सरकार' शब्द के दोनों संविदाकारी राज्यों की कोई भी राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक तथा श्री लंका का सेण्ट्रल बैंक शामिल होंगे।

अनुच्छेद 19**गैर-सरकारी पेन्शन तथा वायिकियां**

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासियों द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से किसी भी पेन्शन (अनुच्छेद 18 में उल्लिखित पेन्शन से भिन्न) अथवा वायिकी पर कर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकता है।

2. 'पेन्शन' शब्द का अर्थ उस नियत-कालिक भुगतान से है जो अतीत की सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अथवा वायिकी-निष्पादन के दौरान पारिश्रमिक खात की क्षतिपूर्ति के रूप में किया गया हो।

3. 'वायिकी' शब्द का अर्थ उस राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त अथवा पूरे प्रतिफल के लिये अदायगियां करने के किसी दायित्व के अधीन, जीवन पर्यन्त अथवा विशिष्ट अथवा निश्चित समय वायिकी के दौरान उल्लिखित समय पर देय होगी।

अनुच्छेद 20**प्राध्यापक तथा अध्यापक**

अगर कोई प्राध्यापक अथवा अध्यापक किसी संविदाकारी राज्य में, किसी अवधि के लिये जो दो वर्ष से अधिक नहीं हो, किसी विश्व-विद्यालय, कालेज, विद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में अध्यापन अथवा अनुसंधान करने के प्रयोजन से अस्थायी यात्रा पर जाता है और अगर वह ऐसे दोरे के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी रहा हो, तो उसे ऐसे अध्यापन अथवा अनुसंधान के लिये प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 21**विद्यार्थी और प्रशिक्षु**

1. कोई विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु जो एक संविदाकारी राज्य की यात्रा से तुरन्त पहले उस संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा रहा हो और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित हो, अपने भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के निमित्त अदायगियां प्राप्त करता हो, तो उस पर उस राज्य में कर नहीं लगेगा बशर्ते कि ऐसी अदायगियां उस राज्य के बाहर के स्रोतों से उत्पन्न हों।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के अन्तर्गत न आने वाले रोजगार से प्राप्त अनुदानों, छात्रवृत्तियों और पारिश्रमिक के संबंध में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित कोई विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु ऐसी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के दौरान, अन्य बातों के अलावा करों के सम्बन्ध में उसी प्रकार की छूटों, राहतों अथवा कटौतियों का हकदार होगा जिस प्रकार की छूट, राहत अथवा कटौतियां उस राज्य के निवासियों को मिलती हैं जिसका कि वह दौरा कर रहा हो।

अनुच्छेद 22**अन्य आय**

एक संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की मर्यादों पर कर, जिनका उल्लेख इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है लेकिन जिन पर उस राज्य में कर लगाया जाता हो, सिर्फ उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 23

पूँजी

1. अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ (2) में उल्लिखित अचल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूँजी पर कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा जिसमें वह सम्पत्ति स्थित हो।

2. तब संपत्ति द्वारा निर्दिष्ट पूँजी जो किसी उद्यम के किसी स्थायी प्रतिष्ठान की व्यावसायिक संपत्ति का एक भाग हो उस पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित हो।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के उपबंधों के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जलयानों और वायुयानों तथा ऐसे जलयानों एवं वायुयानों के संचालन से संबंधित तब संपत्ति पर कर उसी संविदाकारी राज्य में लगाया जाएगा जिसमें उद्यम के कारगर प्रबंध का स्थान स्थित हो।

4. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूँजी के अन्य सभी तत्व केवल उसी राज्य में कराधेय होंगे।

अनुच्छेद 24

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में अपने अपने यहां लागू कानून, आय और पूँजी के कराधान के मामले में लागू रहेंगे जब तक कि इस अभिसमय में इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान न हो। जहां आय अथवा पूँजी पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगता हो वहां इस अनुच्छेद के निम्नलिखित पैराग्राफों के अनुसार दोहरे कराधान से राहत प्रदान की जायगी।

2. भारत से बाहर किसी राज्यक्षेत्र में देय कर को भारतीय कर के प्रति जमा दिखाने की स्वीकृति देने से संबंधित भारत के कानून के उपबंधों के अधधीन (जो इसके सामान्य सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेंगे), श्रीलंका के कानून के अंतर्गत और इस अभिसमय के अनुसार, प्रत्यक्षतः अथवा श्रीलंका के अंतर्गत स्रोतों से प्राप्त लाभों, आय अथवा प्रभाय अभिलाभों (जिसमें किसी लाभांश के मामले में, जिन लाभों में से लाभांश अदा किया जाता है उनके संबंध में देय कर की रकम शामिल नहीं है) पर कटौती द्वारा अथवा श्रीलंका में पूँजी पर देय श्रीलंका के कर को, आय अथवा पूँजी की जिन मदों के संदर्भ में श्रीलंका के कर की संगणना की जाती है उन्हीं मदों के संदर्भ में संगणित किसी भारतीय कर के प्रति जमा के रूप में स्वीकार किया जायगा।

लेकिन जमा दिखायी जाने वाली ऐसी रकम (इस प्रकार की कोई जमा स्वीकार करने से पूर्व यथा संगणित) भारतीय कर से अधिक नहीं होगी जो श्रीलंका स्थित स्रोतों से प्राप्त हुई आय अथवा श्रीलंका में पूँजी के अनुरूप हो, जिससे कि जहां वह निवासी एक ऐसी कंपनी है जिसे भारत में अधिकतर जमा करना है, वहां उपर्युक्त जमा प्रथमतः कंपनी द्वारा भारत में देय आयकर के संदर्भ में जमा मानी जायगी और यदि कोई रकम शेष रहती हो तो वह उसके द्वारा भारत में अदा किये जाने वाले अधिकर के संदर्भ में जमा मानी जायगी।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के प्रयोजन से 'श्रीलंका का देय कर' पदबंध में ऐसी कोई भी राशि शामिल होगी जो किसी वर्ष विशेष के लिए श्रीलंका के कर के रूप में देय हो लेकिन उसमें निम्नलिखित के अंतर्गत उस वर्ष विशेष के किसी भाग के लिए दो गई छूट अथवा कटौती शामिल नहीं होगी:—

(क) निम्नलिखित उपबंधों में से कोई भी एक उपबंध अर्थात् 1979 का श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रीय राजस्व अधिनियम, संख्या 28 की धारा 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 35, जहां तक

कि वे इस अभिसमय पर हस्ताक्षर होने की तारीख को लागू थी और उक्त तारीख के बाद उनमें कोई संशोधन नहीं हुआ हो अथवा केवल ऐसा मामूली संशोधन हुआ हो जिससे उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो; अथवा

(ख) 1978 के बृहत्तर कोलंबो आर्थिक आयोग कानून सं० 4 की धारा 17 के अंतर्गत किया गया कोई करार; अथवा

(ग) कोई भी अन्य उपबंध जो कर की ऐसी छूट अथवा कटौती मंजूर करने के लिए बाद में बनाए जायें, जिसके बारे में सक्षम प्राधिकारियों की यह सहमति हो कि उसका स्वरूप मूलतः वैसा ही है यदि उसमें बाद में संशोधन नहीं किया गया हो अथवा केवल ऐसा मामूली संशोधन किया गया हो जिससे उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

4. श्रीलंका से बाहर किसी राज्य क्षेत्र में देय कर को श्रीलंका के कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति देने संबंधी श्रीलंका के कानून के उपबंधों के अधधीन (जो इसके सामान्य सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेंगे), भारत के कानून के अंतर्गत और इस अभिसमय के अनुसार, प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा भारत में स्रोतों से प्राप्त लाभों, आय अथवा प्रभाय अभिलाभों (किसी लाभांश के मामले में, जिन लाभों में से लाभांश अदा किया जाता है, उनके संबंध में देय कर को छोड़कर) अथवा भारत में पूँजी पर देय भारतीय कर को, आय अथवा पूँजी की जिन मदों के संदर्भ में श्रीलंका के कर की संगणना की जाती है उन्हीं मदों के संदर्भ में संगणित श्रीलंका के किसी कर के प्रति जमा के रूप में स्वीकार किया जायगा।

बशर्त कि ऐसी जमा श्रीलंका के कर से अधिक न हो (ऐसी कोई जमा स्वीकार करने से पूर्व यथा संगणित) जो भारत में स्थित स्रोतों से प्राप्त हुई आय अथवा भारत में पूँजी के अनुरूप हो।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के प्रयोजनार्थ 'देय भारतीय कर' पदबंध में निम्नलिखित के अंतर्गत उस वर्ष के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए मंजूर की गई कर की कोई छूट अथवा कटौती को छोड़कर ऐसी कोई भी रकम शामिल मानी जायगी जो किसी भी वर्ष के लिए भारतीय कर के रूप में देय रही हो:

(क) निम्नलिखित उपबंधों में से कोई भी उपबंध अप्रति, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (4), 10(4क), 10 (15) (iv), 32क, 33क, 35ग, 54ए, 80अग, 80 ज, 80अ, 80 ड, अथवा

(ख) कोई भी अन्य उपबंध जो कर की ऐसी छूट अथवा कटौती मंजूर करने के लिए बाद में बनाए जायें, जिसके बारे में सक्षम प्राधिकारियों की यह सहमति हो कि वह पर्याप्त रूप से समान स्वरूप की हैं, यदि उसमें बाद में संशोधन नहीं किया गया हो अथवा केवल ऐसा मामूली संशोधन किया गया हो जिससे उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

अनुच्छेद 25

सम व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तन्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जायगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है। यह उपबंध अनुच्छेद के उपबंधों के बावजूद, ऐसे व्यक्तियों पर लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के, दूसरे संविदाकारी राज्य में जायी संस्थान पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के वैसे ही कार्य में प्रवृत्त उद्यम पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं किया जायगा कि एक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को वे वैयक्तिक छूट, राहत और कटौतियाँ देने के लिए बाध्य है जिन्हें वह कराधान के परोक्ष के लिए नागरिक हस्तित अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने निवासियों को देता है।

3. जहाँ अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ (1) अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ (7) अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ (6) के उपबंध लागू होते हैं उसे छोड़कर, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गये व्याज, रायल्टियों और अन्य वितरण, ऐसे उद्यम के कर लगने योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती योग्य होंगे मानो वे प्रथमोल्लिखित राज्य के निवासी का अदा किये गये हों। इसी प्रकार, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को किये गये कोई भ्रण, ऐसे उद्यम की कर लगने योग्य पूंजी के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, उन्हीं शर्तों के अधीन कटौती के योग्य होंगे, मानो वे प्रथमोल्लिखित राज्य के निवासी को अनुबंधित किये गये हों।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जायगी जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं में भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हों, जो प्रथमोक्त राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर लागू होती है अथवा हो सकती है।

5. इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी, पक्षों के बीच और प्रकार के करों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 26

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ एक व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर कराधान लगाया जाता है अथवा लगाया जायगा जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपबंधों के होते हुए भी, जिस संविदाकारी राज्य का निवासी है, अथवा यदि उसका मामला उस संविदाकारी राज्य के अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ (1) के अंतर्गत आता है, जिसका वह राष्ट्रिक है, अपना मामला उसके सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। यह मामला उस कार्य की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसके कारण कराधान लगा है और जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो, वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुकूल नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किये गये किसी भी करार को कार्यान्वित किया जायेगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय सीमा क्यों न हो।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयाँ अथवा गंजाएँ उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें, पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी अभिसमय में व्यवस्था नहीं है।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय से सहमति के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्श के माध्यम से, इस अनुच्छेद में उपबंधित पारस्परिक करार कार्यविधि को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त द्विपक्षीय कार्यविधियाँ, नए, पद्धतियाँ और तकनीकों का विकास करेंगे। इसके अनिश्चित, एक सक्षम प्राधिकारी ऊपर उल्लिखित द्विपक्षीय कार्यों और पारस्परिक करार कार्यविधि के कार्यान्वयन को सख्त बनाने के लिए समुचित एक पक्षीय कार्यविधियाँ, नए पद्धतियाँ और तकनीकों विकसित कर सकता है।

अनुच्छेद 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, जो इस अभिसमय के अन्तर्गत आते हैं, जहाँ तक कि उनके अधीन विद्यमान कराधान व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की जालगाजी अथवा अपवर्जन को रोकने के लिए अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हों। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जायगी जिस प्रकार उस राज्य के राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है। तथापि, यदि सूचना को सूचना भेजने वाले राज्य में मूल रूप से गुप्त समझा जाता है तो, उसे ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) प्रकट किया जायगा, जो उन करों के निर्धारण अथवा वसूली, उनके संबंध में प्रवर्तन अथवा अभियोजन अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण में अंतर्गस्त हों, जो इस अभिसमय के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे इस सूचना के सार्वजनिक स्तर पर न्यायालय कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर नहीं करेंगे। सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पद्धतियों और तकनीकों का विकास करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जायगा, जिसमें, जहाँ कहीं उपयुक्त हो कर अपवर्जन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित भार डाला जाय :—

- (क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना।
- (ख) ऐसी सूचना देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिनकी प्रकट करना सरकार की नीति (सरकारी आदेश) के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद 28

राजनियुक्त अधिकार और कौंसलो अधिकारी

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के प्रावधानों के अन्तर्गत इस अभिसमय से राजनयिक अथवा कौंसली अधिकारियों के राज्य कर विषयक विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 29

प्रवर्तन

1. इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जायगा और अनुसमर्थन वस्तावेजों का आवान प्रदान यथा संभव जीव कोलम्बों में किया जायगा।

2. यह अभिसमय, अनुसमर्थन वस्तावेजों का आवान प्रदान होने पर लागू होगा और इसके उपबन्ध—

(क) श्रीलंका में—

(i) 1 अप्रैल, 1980 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के बारे में कर निर्धारण योग्य आय के संबंध में;

(ii) 1 अप्रैल, 1980 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के संबंध में कर निर्धारण योग्य पूंजी के संबंध में।

(ख) भारत में—

(i) 1 अप्रैल, 1981 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के संबंध में कर निर्धारण योग्य आय के संबंध में;

(ii) 1 अप्रैल, 1980 को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के संबंध में कर लगने योग्य पूंजी के संबंध में,

लागू होंगे।

3. आय के दोहरे कराधान से राहत पाने तथा उसके अपाकरण के लिए श्रीलंका की सरकार तथा भारत सरकार के मध्य हुआ करार, जिस पर 10 नवम्बर, 1956 को हस्ताक्षर किये गये थे, समाप्त हो जायेगा और आय पर उन करों के संबंध में, जिन पर इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के उपबंधों के अनुसार वर्तमान अभिसमय लागू होता है, निष्प्रभावी हो जायेगा।

अनुच्छेद 30

समाप्ति

यह अभिसमय अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, परन्तु संविवाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद से शुरू होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष में 30 जून, को या उससे पहले, राजनयिक माध्यम से दूसरे संविवाकारी राज्य को, समाप्ति का लिखित नोटिस दे सकेगा।

ऐसी स्थिति में यह अभिसमय—

(क) श्रीलंका में—

(i) जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल मास के प्रथम दिन को, अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण योग्य आय के संबंध में;

(ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण योग्य पूंजी के संबंध में

(ख) भारत में—

(1) जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल मास के प्रथम दिन को शुरू होने वाले कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण योग्य आय के संबंध में;

(2) जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिस दिया गया हो, उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में 1 अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण योग्य पूंजी के संबंध में निष्प्रभावी हो जायेगा।

जिसके साध्य में, इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये हैं।

नई दिल्ली में वर्ष 1982 के जनवरी मास के 27 दिन को सिंहल, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो दो प्रतियां में किया गया, इसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी
गणराज्य की सरकार की ओर से

प्रोटोकॉल

आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजस्व अपवर्जन को रोकने के लिए एक अभिसमय में शामिल हो जाने पर श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार, उक्त अभिसमय पर हस्ताक्षर करते समय निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हो गई हैं, जो उक्त अभिसमय के अतिरिक्त अंग बनेंगे—

(क) अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ (ज) और (घ) में उल्लिखित अवधि का विस्तार सीमा से बड़ा अर्थ दिया जायेगा जो, इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के बाद श्रीलंका प्रांत, दोहरे कराधान से बचने के लिए किये गये किसी अभिसमय में, किसी भवन स्थल, निर्माण अथवा संयोजन परियोजना अथवा सेवाएँ प्रदान करने से संबंधित स्थायी संस्थान के संबंध में अनुच्छेद में शामिल की गई अधिक नम्बो अवधि के समान होगी।

(ख) अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ (2) में निर्धारित जहाजरानों से संबंधित लाभों पर कर लगाने का आधार इस अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के बाद श्रीलंका प्रांत दोहरे कराधान से बचने के लिए किये गये किसी अभिसमय में की गई व्यवस्था से कम अनकूल नहीं होगा।

जिसके साध्य में, इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष 1982 के जनवरी मास के 27 दिन को सिंहल, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो दो प्रतियां में किया गया, इसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक होंगे, अर्थ निरूपण में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

ह०

ह०

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी
गणराज्य की सरकार की ओर से

[फा० सं० 501/1/77-वि० सं० प्र०]
आर० आर० खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 1983

INCOME-TAX

G.S.R. 342(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital has been ratified and the instruments of ratification exchanged as required by Article 29 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and Section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

CONVENTION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
ANDTHE GOVERNMENT OF THE
DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

for
the avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal
evasion with respect to taxes
on income and on capital

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF
THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI
LANKA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXA-
TION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON
CAPITAL

The Government of the Republic of India and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed as follows:

ARTICLE 1

Personal Scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

Taxes Covered

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which this Convention shall apply are:—

(a) In Sri Lanka:

(i) the income tax, including the income tax based on the turnover of enterprises licensed by the Greater Colombo Economic Commission; and

(ii) the wealth tax;
(hereinafter referred to as "Sri Lanka tax")

(b) In India:

(i) the income tax including any surcharge thereon;

(ii) the surtax; and

(iii) the wealth tax.

(hereinafter referred to as "Indian tax")

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any important changes which have been made in their respective taxation laws.

ARTICLE 3

General Definitions

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Sri Lanka or India as the context requires;

(b) the term "person" includes an individual a company and any other body of persons;

(c) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for the tax purposes;

(d) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(e) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(f) the term "national" means:

(i) an individual possessing the nationality of a Contracting State;

(ii) a legal person, partnership or an association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

(g) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Sri Lanka, the Commissioner-General of Inland Revenue;

(ii) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue).

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

ARTICLE 4

Fiscal Domicile

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
 - (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
 - (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
 - (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph (1) of this Article a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" shall include especially:
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office;
 - (d) a factory;
 - (e) a workshop;
 - (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
 - (g) an agricultural or farming estate or plantation;
 - (h) a building site or construction or assembly project which exists for more than 183 days;
 - (i) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel, where activities of that nature continue within the country for a period or periods aggregating more than 183 days within any twelve month period.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
 - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
 - (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise.
4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom paragraph (6) of this

Article applies—shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of independent status to whom paragraph (6) of this Article applies.

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

Income from Immovable Property

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph (1) of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs (1) and (3) of this Article shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

ARTICLE 7

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to—
 - (a) that permanent establishment,
 - (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment, or
 - (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

The provisions of sub-paragraphs (b) and (c) above shall not apply if the enterprise proves that such sales or activities are not attributable to the permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph (3) of this Article, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on money lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise by way of interest on money lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts nothing in paragraph (2) of this Article shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment shall, however, be such that the result will be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

Shipping and Air Transport

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place effective management of the enterprise is situated.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph (1), profits derived from the operation of ships in international traffic may be taxed in the Contracting State in which such operation is carried on; but the tax so charged shall not exceed 50 per cent of the tax otherwise imposed by the internal law of that State.

Provided that for the purpose of the calculation of the tax, such profits shall be deemed to be an amount not exceeding the rates presently provided in the taxation laws of the respective States for the computation of such profits

3. The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall likewise apply in respect of profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency

of any kind by enterprises engaged in the operation of ships or aircraft in international traffic.

4. For the purpose of paragraph 1, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

5. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or if there is no such home harbour, in the State of which the operator of the ship is a resident.

ARTICLE 9

Associated Enterprises

1. Where:—

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

ARTICLE 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, mining shares, founders' shares or other rights not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of this Article interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

- (a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof, or
- (b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the state in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs (1) to (3) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In such case the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalty the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of or the right to the any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or tapes for television or broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

6. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in paragraph (2) of Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State including such gains from the alienation of such a permanent establishment alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of stocks shares of a company may be taxed in the Contracting State in which they have been issued.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs (1) to (4) of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

6. The term "alienation" means the sale, exchange, transfer, or relinquishment of the property or the extinguishment of any rights therein or the compulsory acquisition thereof under any law in force in the respective Contracting States.

ARTICLE 14

Independent Personal Services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless his stay in the other Contracting State is for a period or periods exceeding in the aggregate 120 days within any 12 months period, when such income may also be taxed in the other Contracting State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment is exercisable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if :

- (a) The recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any 12 month period ; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft in international traffic, may be taxed only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

ARTICLE 16

Directors' Fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 17

Artistes and Athletes

1. Notwithstanding the provisions of Article 14 and 15, income derived by public entertainers (such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised :

Provided that such income shall not be taxed in the said Contracting State if the visit of the public entertainers or athletes to that State is directly or indirectly supported wholly or substantially, from the public funds of the Government of the other Contracting State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. For the purposes of this Article, the term "Government" includes a State Government, a political sub-division or a local authority of either Contracting State.

ARTICLE 18

Government Service

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by the Government of a Contracting State to an individual in respect of services rendered to that State or a local authority thereof shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :

- (i) is a national of that State, or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. Any pension paid by the Government of one of the Contracting States to any individual may be taxed in that Contracting State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a local authority thereof.

4. For the purposes of this Article, the term "Government" shall include any State Government or local authority of either Contracting State, the Reserve Bank of India and the Central Bank of Ceylon.

ARTICLE 19

Non-Government Pensions and Annuities

1. Any pension (other than a pension referred to in Article 18) or annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of services rendered in the past or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

ARTICLE 20

Professors and Teachers

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

ARTICLE 21

Students and Apprentices

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present

in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. In respect to grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph (1) of this Article a student or business apprentice described in paragraph (1) of this Article shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting.

ARTICLE 22

Other Income

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Article of this Agreement in respect of which he is subject to tax in that State shall be taxable only in that State.

ARTICLE 23

Capital

1. Capital represented by immovable property referred to in paragraph (2) of Article 6 may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment of an enterprise may be taxed in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of this Article, ships and aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

ARTICLE 24

Elimination of Double Taxation

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income and capital in the respective Contracting States except when express provision to the contrary is made in this Convention. When income or capital is subject to tax in both Contracting States, relief from double taxation shall be given in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. Subject to the provisions of the law of India regarding the allowance as a credit against Indian tax of tax payable in a territory outside India (which shall not affect the general principle hereof) Sri Lanka tax payable under the law of Sri Lanka and in accordance with this Convention whether directly or by deduction on profits, income or chargeable gains from sources within Sri Lanka (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) or capital in Sri Lanka shall be allowed as a credit against any Indian tax computed by reference to the same items of income or capital by referred to which the Sri Lanka tax is computed:

Provided that such credit not exceed Indian tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within Sri Lanka or to capital in Sri Lanka, so however, that where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income tax payable by the company in India, and as to the balance if any against surtax payable by it in India.

3. For the purposes of paragraph (2) of this Article, the term "Sri Lanka tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Sri Lanka tax for any year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof under :

- (a) any of the following provisions, that is to say sections 11, 16, 17, 18 19 20 21 22 and 85 of the Sri Lanka Inland Revenue Act, No. 28 of 1979 so far as they were in force on, and have not been modified since, the date of the signature of this Convention, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character ; or
- (b) any agreement entered into under section 17 of the Greater Colombo Economic Commission Law No. 4 of 1978; or
- (c) any other provisions which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which is agreed by the competent authorities to be of a substantially similar character, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

4. Subject to the provisions of the law of Sri Lanka regarding the allowance as a credit against Sri Lanka tax of tax payable in a territory outside Sri Lanka (which shall not affect the general principle hereof) Indian tax payable under the law of India and in accordance with the Convention, whether directly or by deduction, on profits, income or chargeable gains from sources within India (excluding in the case of a dividend, tax payable in respect of the profits out of which the dividend is paid) or capital in India shall be allowed as a credit against any Sri Lanka tax computed by reference to the same items of income or capital by reference to which the Sri Lanka's tax is computed:

Provided that such credit shall not exceed Sri Lanka tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within India or to capital in India.

5. For the purpose of paragraph (4) of this Article, the term "Indian Tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax for any year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof under :

- (a) any of the following provisions, that is to say sections 10(4), 10(4A), 10(15)(iv), 32A, 33A 35C 54E, 80CC, 80HH, 80J, 80K of the Income Tax Act, 1961; or
- (b) any other provisions which may subsequently be made granting an exemption or reduction of tax which is agreed by the competent authorities to be of a substantially similar character if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.

ARTICLE 25

Non-Discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burden some than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that

other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph (1) of Article 9, paragraph (7) of Article 11 or paragraph (6) of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

ARTICLE 26

Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph (1) of Article 25 to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. The competent authorities, through consultations, shall develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in this Article. In addition, a competent authority may devise appropriate unilateral procedures, conditions, methods and techniques to facilitate the above-mentioned bilateral actions and the implementation of the mutual agreement procedure.

ARTICLE 27

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by

the Convention, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall through consultation develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchanges of information shall be made, including, where appropriate, exchanges of information regarding tax avoidance.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (order public).

ARTICLE 28

Diplomatic Agents and Consular Officials

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 29

Entry into Force

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Colombo as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

- In Sri Lanka—
 - in respect of income assessable for any year of assessment commencing on or after 1st April, 1980;
 - in respect of capital assessable for any year of assessment commencing on or after 1st April, 1980.
- In India—
 - in respect of income assessable for any year of assessment commencing on or after 1st April, 1981;
 - in respect of capital assessable for any year of assessment commencing on or after 1st April, 1980.

3. The Agreement between the Government of Ceylon and the Government of India for relief from or the avoidance of double taxation of income, signed on 10th September, 1956, shall terminate and cease to have effect as respects taxes on income to which the present Convention applies in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article.

ARTICLE 30

Termination

This Convention shall remain in force indefinitely but either Contracting State may, on or before June 30 in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination.

In such event, the Convention shall cease to have effect—

(a) In Sri Lanka—

- (i) in respect of income assessable for any year of assessment commencing on or after 1st April in the calendar year next following that in which such notice is given ;
- (ii) in respect of capital assessable for any year of assessment commencing on or after 1st April in the calendar year next following that in which such notice is given.

(b) In India—

- (i) in respect of income assessable for the assessment year commencing on the 1st day of April in the second calendar year next following the calendar year in which the notice is given, and subsequent years ;
- (ii) in respect of capital assessable for any year of assessment commencing on or after 1st April in the calendar year next following that in which such notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in duplicate at New Delhi this 27th day of January, 1982, in the Sinhala, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

Sd/-
(PRANAB MUKHERJEE)
For the Government of
The Republic of India.

Sd/-
(RONNIE DE MAL)
For the Government of the
Democratic Socialist Republic
of Sri Lanka.

PROTOCOL

The Government of the Republic of India and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, having entered into a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, have agreed, at the time of signing the said Convention, on the following provisions which shall constitute an integral part thereof :

- (a) The length of the period referred to in sub-paragraphs (h) and (i) of Article 5 shall be construed as identical to any period of longer duration incorporated in the Article on Permanent Establishment in relation to a building site, construction or assembly project or the furnishing of services, in any Convention for the avoidance of double taxation entered into by Sri Lanka after the signing of this Convention.
- (b) the basis of taxing shipping profits set out in paragraph 2 of Article 8 shall not be less favourable than that provided in any Convention for the avoidance of double taxation entered into by Sri Lanka after the signing of this Convention.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at New Delhi this 27th day of January, 1982, in the Sinhala, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

Sd/-
(PRANAB MUKHERJEE)
For the Government of
The Republic of India.

Sd/-
(RONNIE DE MAL)
For the Government of the
Democratic Socialist Republic
of Sri Lanka.

[F. No. 501/1/77-FTD]
R. R. KHOSLA, Jt. Secy.